पुटिंग नेबर्स फर्स्ट

लेखक-सुजान आर चिनॉय (महानिदेशक, मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नई दिल्ली)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

21 फरवरी, 2020

"भारत ने अपने पड़ोसियों से आपसी संबंध को बेहतर बनाये बगैर ही उदारता की भावना से दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है।"

फरवरी में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की भारत की यात्रा ने एक अच्छे पड़ोसी के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत की। विदित हो कि भारत का श्रीलंका के साथ संस्कृति, धर्म, आध्यात्मिकता, कला और भाषा से संबंधित ऐतिहासिक संबंध रहा है। अधिक प्रासंगिक रूप से पिछले अप्रैल में श्रीलंका में ईस्टर के समय हुए हमलों के बाद से दोनों देशों का आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख एक समान ही देखने को मिला है।

कई बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ जैसे चेन्नई और जाफना के बीच सीधी उड़ानें, नौका सेवाओं को फिर से शुरू करना, भारत की क्रेडिट की नई लाइनें और आंतरिक रूप से विस्थापित, बेघर और भूमिहीन लोगों के लिए घरों का निर्माण, संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। महिंद्रा राजपक्षे और उनके भाई राष्ट्रपति गोटाबाया दोनों ने सत्ता संभालने के बाद भारत को ही अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चुना था।

महिंद्रा ने 8 फरवरी को एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीति को बहुत सराहा और कहा कि इस नीति की वजह से दोनों राष्ट्रों के बीच एक मजबूत रिश्ता सक्षम हो सका है। भारत द्वारा उपहार में दी गई 280 एम्बुलेंस के माध्यम से दी जाने वाली मुफ्त आपातकालीन सेवाओं के लिए श्रीलंका में उत्साह का माहौल है, जो अब देश के नौ प्रांतों में से आठ में चालू है। कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास और त्रिंकोमाली तेल भंडारण टैंक के प्रस्तावित संयुक्त विकास में भारत, जापान और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय सहयोग के लिए आज बेहतर संभावनाएँ हैं।

पिछले साल के आम चुनावों के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा राष्ट्रपति इब्राहिम सोलीह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए जून 2019 में मालदीव में हुई थी, जिन्होंने अपनी "इंडिया फर्स्ट पॉलिसी" के माध्यम से भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया है। दिसंबर 2018 में भारत पहला ऐसा देश था जहाँ सोलिह ने यात्रा की थी और ये अपने पूर्ववर्ती अब्दुल्ला यामीन के भारत विरोधी-विचार से काफी दूर थे। पद संभालने के तुरंत बाद सोलिह की सरकार ने एक विवादास्पद 2015 कानून को रद्द कर दिया, जो विदेशियों, विशेष रूप से चीन को मनमाने ढंग से स्वयं के द्वीपों को खरीदने की अनुमति देता था।

मोदी की यात्रा के दौरान 180 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें तटीय निगरानी रडार प्रणाली और मालदीव का राष्ट्रीय रक्षा बलों का समग्र प्रशिक्षण केंद्र शामिल था। भारत की पड़ोस नीति की सफलता में ये विशेष महत्व रखते हैं। भारत की जल आपूर्ति और सीवरेज के लिए लगभग 800 मिलियन डॉलर और अन्य क्षमता-निर्माण परियोजनाओं के लिए ऋण की पेशकश हमारे आर्थिक संबंधों में मजबूती एक मुद्दा रहा है। इसके अलावा, आतंकवाद और कट्टरता आम चिंता का विषय बन गया है।

भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिकोणीय एनएसए-स्तरीय संवाद के रूप में त्रिपक्षीय दोस्ती (DOSTI) नौसेना अभ्यास को फिर से शुरू करने के समझौते ने यामीन युग से खर हुए संबंध को पुनः सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है।

मोदी के दूसरे कार्यकाल में भारत की पड़ोस नीति में एक नई प्रतिबद्धता के भरपूर संकेत देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल सितंबर में, भारत और नेपाल ने संयुक्त रूप से दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस-बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन का भारत में मोतिहारी से नेपाल में अमलेखगंज तक उद्घाटन किया। खुद पीएम के.पी. ओली ने स्वीकार किया कि प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना, जो नेपाल को सस्ती लागत पर स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराएगी, यह तय समय से पहले ही पूरा हो गया है, जो इस धारणा को गलत ठहराता है कि भारतीय परियोजनाओं में हमेशा देरी होती है। भारत गोरखा और नुवाकोट जिलों में "बिल्ड बैक बेटर" के साथ घरों के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दे रहा है, जो कि आपदा रोधी अवसंरचना (CDRI) के लिए मोदी के स्पष्ट आह्वान को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में है।

भूगोल अंतर-निर्भरता बनाने में एक निर्धारित भूमिका निभाता है। अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तरह नेपाल भी चीन के साथ घनिष्ठ संबंध चाहता है, लेकिन आज भी इस बात की अधिक सराहना हो रही है कि एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक और विकासात्मक भागीदार के रूप में भारत की भूमिका अद्वितीय और अपरिहार्य है।

मोदी और शेख हसीना के बीच अच्छे वार्ताओं से बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध एक मॉडल साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं, जो उच्च स्तर के आदान-प्रदान, आपसी विश्वास और सुरक्षा मामलों पर सहयोग को बढ़ाते हैं। सीमा पर गोलीबारी की घटनाएँ, हालांकि दुर्लभ हैं, सार्वजनिक धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसे संवेदनशीलता के साथ नियंत्रित करने की आवश्यकता है। भारत-भूटान की दोस्ती जलविद्युत क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सहयोग के साथ गहरी हो रही है। विशेष रूप से, केंद्रपीठ मंगदेछु परियोजना (750 मेगावाट) पिछले साल तय समय पर पूरी हुई। भूटान और आसपास के अन्य जगहों पर RuPay कार्ड की शुरुआत से आर्थिक और लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। जब भारत शीघ्र ही म्यांमार आईएनएस सिंधुवीर को सौंप देगा, जो किलो क्लास पनडुब्बी है, तो यह उच्चतर सीमा तक सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा।

मोदी की पड़ोस नीति समावेशी विकास, वृद्धि और समृद्धि के लिए उनके "सबका साथ, सबका विकास" के दृष्टिकोण पर आधारित है। दक्षिण एशिया में 1.8 बिलियन लोग और लगभग 3.47 ट्रिलियन डॉलर की कुल जीडीपी है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था अब तक सबसे बड़ी रही है। दक्षिण एशिया में काफी संभावनाएँ हैं, लेकिन पाकिस्तान द्वारा इसे पूरा नही होने दिया जा रहा है। इस वजह ने न केवल भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए भूमि के पारगमन मार्ग से वंचित कर दिया है, बल्कि गरीबी, अशिक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ आम संघर्ष को केंद्र में रखने के मोदी के प्रयासों को भी विफल कर दिया है।

इसने सार्क के भीतर असंगत मामलों को उठाते हुए आतंकवाद को खत्म करने और अंतर-दक्षिण एशियाई व्यापार के अयोग्य तर्क को खारिज करते हुए सहयोग को रोक दिया है। इस्लामाबाद ने मोदी द्वारा प्रस्तावित सार्क उपग्रह परियोजना से बाहर होने का फैसला किया था और इसे अंततः 2017 में पाकिस्तान की भागीदारी के बिना ही लॉन्च करना पड़ा था। पाकिस्तान ने नवंबर 2014 में 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में एक स्पॉइलर (छिन्न-भिन्न करने वाला) की भूमिका निभाई, जिसने सार्क सदस्य देशों के बीच यात्री और मालवाहक वाहनों के आवागमन के नियमन के लिए प्रस्तावित मोटर वाहन समझौते की प्रगति पर लगाम लगा दी।

कनेक्टिविटी पर पाकिस्तान की दखल अंदाजी अफगानिस्तान की दक्षिण एशिया के अन्य देशों के साथ जुड़ने की क्षमता को बाधित करती है। इस वजह से भारत और अफगानिस्तान के बीच हवाई गलियारा व्यापार संबंधों की संभावना भी पूरी नहीं हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया तनावों ने चाबहार बंदरगाह की स्थिरता को अंधकार में डाल दिया है जो कि अफगानिस्तान में एक वैकल्पिक समुद्री आपूर्ति मार्ग के रूप में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है।

अफगानिस्तान में बहुत जरूरी बुनियादी ढाँचे और क्षमताओं के निर्माण में हाल के वर्षों में भारत की सक्रिय भूमिका व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। मोदी के कार्यकाल में रक्षा सहयोग भी बहुत गहरा हो गया है। भारत आर्थिक समृद्धि के माध्यम से अफगानिस्तान को स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वैसे भी अफगानिस्तान का भाग्य दक्षिण एशिया के साथ ही जुड़ा है।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी के दूसरे कार्यकाल में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के कुछ प्रमुख पहलुओं को रेखांकित किया है। उन्होंने भारत द्वारा नई सहायता के साथ सुरक्षा चुनौतियों का जवाब देने और नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और विस्तारित पड़ोस में मानवीय सहायता प्रदान करने और आपदा राहत कार्यों का संचालन करने की इच्छा व्यक्त की। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है भारत द्वारा विकासात्मक सहायता का विस्तार और सहयोगी साझेदारी के आधार पर परियोजना निष्पादन में सुधार के लिए की गई निरंतर प्रगति।

सार्क में ठहराव पूरी तरह से पाकिस्तान के कारण है। फिर भी, 2014 और 2018 के बीच छह दक्षिण एशियाई देशों में भारत की विकास सहायता 21,100 करोड़ रुपये से अधिक रही थी। अन्य क्षेत्रीय समूह बिम्सटेक ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस साल फरवरी में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार के प्रतिनिधियों और बचाव दलों ने उत्साहपूर्वक ओडिशा के पुरी में रामचंडी बीच पर आयोजित आपदा प्रबंधन अभ्यास में भाग लिया। अगस्त 2018 में काठमांडू में सभी सात राष्ट्रों द्वारा भाग लेने वाले चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक ग्रिड इंटरकनेक्शन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर सीमा पार से बिजली व्यापार के लिए एक मार्ग प्रदान करता है।

BIMSTEC और इसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भारत के फोकस ने दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में सहकारी विकास को बढ़ावा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने का काम किया है।

यदि पाकिस्तान आतंकवाद और नरसंहार के राह से खुद को अलग कर लेता है, तो वह एक दिन दूसरों के साथ मिलकर क्षेत्रीय सहकारी प्रयासों में एक जिम्मेदार अभिनेता के रूप में जरूर शामिल हो सकता है, जिसका उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी), जिसमें विशेष रूप से गरीबी तथा भुखमरी का उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ पानी, ऊर्जा, लैंगिक समानता और 2030 तक दक्षिण एशिया के लाखों लोगों के लिए रोजगार को सुनिश्चित करना शामिल है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. भारत और श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य हैं?

(a) हाल ही में भारत ने श्रीलंका को मुफ्त आपातकालीन सेवा हेतु 280 एम्बुलेंस प्रदान किए हैं।

(b) कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का विकास और त्रिंकोमाली तेल भंडारण टैंक भारत, जापान और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय समझौता है।

(c) त्रिपक्षीय दोस्ती नौ-सेना अभ्यास भारत, जापान और श्रीलंका का संयुक्त सैन्याभ्यास है।

(d) नव निर्वाचित श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पहली विदेश यात्रा भारत में की।

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Which of the following statement is incorrect in the perspective of India and Sri Lanka?

(a) Recently India has provided 280 ambulances for free emergency service to Sri Lanka.

(b) Development of East Container Terminal at Colombo Port and Trincomalee Oil Reserve Tank is a tripartite agreement between India, Japan and Sri Lanka.

(c) The trilateral Naval Exercise Dosti is a joint exercise of India, Japan and Sri Lanka.

(d) The newly elected Sri Lankan President made the first foreign trip to India.

नोट : 20 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'भारत की पड़ोसियों के प्रति नीति में पिछले कुछ वर्षों में आया बदलाव इसके लिए सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम पैदा करने वाला है। 'आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

'Changes in India's policy towards her neighbors in the last few years are going to produce positive and negative consequences for her. To what extent do you agree with this statement? Discuss. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।